

सिंहस्थ कुंभ मेले पर दिए गए नफरत फैलाने वाले बयान से मंत्री नितेश राणे मुश्किल में-अल्पसंख्यक आयोग भेजेगा नोटिस

रिपोर्ट: जमीर काज़ी । मुंबई
धार्मिक घृणा फैलाने वाले बयानों के कारण बार-बार विवादों में घिरने वाले मत्स्य उद्योग व बंदरगाह विकास मंत्री नितेश राणे की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ने वाली हैं। नाशिक-त्र्यंबकेश्वर में २०२७ में होने वाले सिंहस्थ कुंभ मेले में केवल हिंदुओं की ही दुकानें लगनी चाहिएं और अन्य धर्मों के लोगों को स्थान नहीं दिया जाना चाहिए - ऐसे बयान के कारण महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग जल्द ही उन्हें नोटिस भेजने वाला है। आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान ने यह दावा करते हुए कहा कि राणे के बयान से राज्य का सामाजिक सौहार्द बिगड़ रहा है।



प्यारे खान ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, नितेश राणे बार-बार विवादास्पद बयान देकर महाराष्ट्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस देश और राज्य में एकता का संदेश दे रहे हैं, वहीं राणे अपने बयानों से माहौल खराब कर रहे हैं। हिंदू-मुस्लिम एकता बनाए रखने के लिए दोनों नेता प्रयासरत हैं, लेकिन राणे के बयान से समाज

में दूरी और तनाव बढ़ रहा है। इस मुद्दे पर मैं जल्द ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से चर्चा करूंगा। मुख्यमंत्री ने पहले भी कई विवादित नेताओं को किनारे किया है, और जल्द ही उस सूची में राणे का नाम भी शामिल होगा। अल्पसंख्यक आयोग की ओर से उन्हें नोटिस भेजा जाएगा, ऐसा प्यारे खान ने स्पष्ट किया। विवाद आखिर है क्या? गुरुवार को नाशिक दौरे पर

गए मंत्री नितेश राणे ने सिंहस्थ कुंभ मेले में लगने वाली दुकानों के संदर्भ में कहा था - कुंभ मेला हिंदू धर्मावलंबियों का उत्सव है, इसलिए यहां केवल हिंदुओं की ही दुकानें लगनी चाहिएं। गोल टोपी और दाढ़ी वाले यहां क्या करने आएंगे? दुकान के बाहर नाम बदलकर अंदर कोई और व्यक्ति बैठा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। त्र्यंबकेश्वर परिसर में अन्य धर्मों की दुकानें क्यों दिखाई देती

हैं? हम क्या उनके प्रार्थना स्थलों के पास जाकर सामान बेचते हैं? ऐसा विवादित बयान देते हुए राणे ने कहा कि कुंभ मेले के संदर्भ में हिंदू समाज और साधु-संतों को सतर्क रहना चाहिए। इसी बयान पर महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान ने आपत्ति जताई है और कार्रवाई की दिशा में कदम बढ़ाया है।

राज्य की सभी वक्फ मस्जिदों, दरगाहों, कब्रिस्तानों की ५ दिसंबर तक उम्मीद पोर्टल पर १०० प्रतिशत रजिस्ट्रेशन करें ना.समीर काज़ी का आह्वान; गाफिल न रहें आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं

बीड (प्रतिनिधि) राज्य की सभी वक्फ के अंतर्गत रजिस्टर्ड मस्जिदों, दरगाहों, कब्रिस्तानों की ५ दिसंबर २०२५ तक 'उम्मीद पोर्टल' पर रजिस्ट्रेशन करने का आह्वान महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष समीर काज़ी ने किया है। उम्मीद पोर्टल पर सभी दस्तावेजों का रजिस्ट्रेशन होना अत्यंत आवश्यक और सुरक्षित है। इसलिए किसी भी प्रकार की लापरवाही, हथगथ किए बिना आज ही रजिस्ट्रेशन करा लें। दस्तावेजों से संबंधित कोई समस्या हो तो तुरंत वक्फ बोर्ड के कार्यालय से संपर्क करें, उन्हें हरसंभव मदद की जाएगी, ऐसा भी ना. समीर काज़ी ने स्पष्ट किया है।

राज्य की वक्फ संपत्ति का प्रबंधन पारदर्शी और डिजिटल तरीके से करने के लिए उम्मीद पोर्टल पर यह रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। राज्य की सभी मस्जिदों, दरगाहों, कब्रिस्तानों और अन्य वक्फ संस्थाओं को अपनी संस्था के आवश्यक दस्तावेज जैसे रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र,

मालिकाना हक के दस्तावेज, ट्रस्टी बोर्ड की जानकारी आदि उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। इस उपक्रम से राज्य की वक्फ संपत्ति की उचित रिकॉर्ड बही तैयार होगी तथा धोखाधड़ी, अनधिकृत उपयोग और गड़बड़ियां पर अंकुश लगेगा, ऐसा ना. समीर काज़ी ने बताया। उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए ५ दिसंबर २०२५ अंतिम तिथि है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगा। जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी ऐसी संस्थाएं अनधिकृत मानी जा सकती हैं। इसलिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन से संबंधित अधिक जानकारी व मार्गदर्शन के लिए वक्फ बोर्ड की



आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं या जिला वक्फ बोर्ड के कार्यालय से संपर्क करें, ऐसा आह्वान अध्यक्ष ना. समीर काज़ी ने किया है। वक्फ बोर्ड के सभी कार्यालय छुट्टी के दिन भी खुले रहेंगे महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड के राज्य के सभी मुख्य और जिला कार्यालय ५ दिसंबर २०२५ तक खुले रहेंगे। सभी कार्यालयों में नियमित कामकाज के डेस्क बंद कर हर डेस्क पर ५ दिसंबर तक केवल उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन से संबंधित कामकाज चालू रहेगा। इस अवधि में सभी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और पूर्णकालिक सभी कार्यालय खुले रहेंगे, ऐसा काज़ी ने बताया। तेरह सदस्यों की गैर-सरकारी समिति नि यु क्त ; एनजीओ आगे आए सेंटर शुरू करने के लिए

- समीर काज़ी
राज्य की वक्फ के अंतर्गत रजिस्टर्ड मस्जिदों, दरगाहों, कब्रिस्तानों की उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए वक्फ बोर्ड की ओर से १३ सदस्यों की गैर-सरकारी समिति नियुक्त की गई है। इसमें जमीयत अरशद मदनी ग्रुप के २, जमीयत महमूद मदनी ग्रुप के २, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के २, तबलीग जमात के २, काज़ी सेवा संघ २, बरेलवीवाले २ और वक्फ बोर्ड का १ नोडल अधिकारी ऐसे १३ सदस्य शामिल होंगे। यह समिति रजिस्ट्रेशन के लिए मार्गदर्शन करेगी तथा दस्तावेजों से संबंधित समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेगी। साथ ही बीड जिले सहित राज्य की सामाजिक सेवा संस्थाओं (एनजीओ) को रजिस्ट्रेशन के काम में गति देने के लिए स्वयं पहल कर उम्मीद पोर्टल सेंटर शुरू करना चाहिए। वहां कंप्यूटर पर काम करने वाले लड़कों को राज्य वक्फ बोर्ड मानदेय देगा, ऐसा समीर काज़ी ने बताया है।

स्वहित से अधिक किसानों का हित महत्वपूर्ण-विधायक संदीप क्षीरसागर

गजानन सहकारी चीनी कारखाने के पेराई सीजन का संत-महंतों के हाथों शुभारंभ



बीड, ९ नवंबर - गजानन सहकारी चीनी कारखाने के वर्ष २०२५-२६ के मोळी पूजन और पेराई (गळीत) सीजन का शुभारंभ रविवार (९ नवंबर) को किया गया। इस अवसर पर विधायक संदीप क्षीरसागर ने कहा कि स्वहित से अधिक किसानों का हित साधना आवश्यक है, और इसी सोच को ध्यान में रखकर १० वर्षों से बंद पड़े गजानन सहकारी चीनी कारखाने को अथक प्रयासों से पुनः शुरू किया गया है। उन्होंने

कहा कि क्षेत्र के गन्ना उत्पादक किसानों के विकास के लिए वे और गजानन चीनी कारखाना सदैव प्रतिबद्ध हैं। श्री गजानन सहकारी चीनी कारखाने के मोळी पूजन और पेराई सीजन का शुभारंभ रविवार (९ नवंबर) को संत-महंतों के हाथों अत्यंत उत्साहपूर्वक किया गया। इस अवसर पर श्रीक्षेत्र नारायणगड के महंत ह.भ.प. शिवाजी महाराज, मंगलमूर्ति देवस्थान के ह.भ.प. अमृताश्रमजी महाराज,

श्रीक्षेत्र ढेकळे महाराज संस्थान बेलखंडी (पाटोदा) के ह.भ.प. भक्तीदास महाराज, साधकाश्रम तिप्पटवाडी के ह.भ.प. ज्ञानेश्वर माऊली महाराज सहित अन्य संत-महंत उपस्थित थे। साथ ही, पूर्व विधायक सय्यद सलीम, राष्ट्रवादी कांग्रेस (शरदचंद्र पवार) पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेंद्र मस्के सहित अनेक मान्यवर और क्षेत्र के गन्ना उत्पादक किसान बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

गेवराई नगराध्यक्ष पद के लिए ओबीसी उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे-प्रस्थापित नेताओं को दिखाएंगे अपनी ताकत

ओबीसी समाज का निर्णय-ओबीसी का वोट अब सिर्फ ओबीसी उम्मीदवारों को ही

काज़ी अमान / गेवराई
गेवराई नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए ओबीसी वर्ग से उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरकर राजनीति में प्रस्थापित नेताओं को अपनी ताकत दिखाने वाले हैं, ऐसी जानकारी पूर्व विधायक डॉ. नारायणराव मुंडे के सुपुत्र तथा ओबीसी युवा नेता सुघोष मुंडे ने दिव्य लोकप्रभा से बातचीत में दी।



इस संबंध में सुभाष मुंडे ने बताया कि गेवराई शहर के महात्मा फुले विद्यालय में हाल ही में सकल ओबीसी समाज की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी स्थानीय स्वराज्य संस्था (नगर परिषद) चुनाव में प्रस्थापित राजनेताओं के विरोध में ओबीसी उम्मीदवार खड़ा किया जाएगा ताकि ओबीसी समाज की राजनीतिक ताकत दिख सके।

गेवराई तालुका की राजनीति में मौजूद दो प्रमुख गटों (समूहों) ने जो उम्मीदवार नगराध्यक्ष पद के लिए जनता के समक्ष रखा है, उसे लोगों ने पसंद नहीं किया है। इसलिए ओबीसी समाज ने एक नए चेहरे को मौका देने का निश्चय किया है। इस बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया गया कि ओबीसी समाज का वोट अब केवल ओबीसी उम्मीदवारों को ही दिया जाएगा।

प्रस्थापित नेताओं द्वारा जनता पर थोपे गए उम्मीदवारों को कड़ी टक्कर देने की क्षमता ओबीसी उम्मीदवारों में है, ऐसा विश्वास उपस्थित सर्व ओबीसी कार्यकर्ताओं ने व्यक्त किया। बैठक में यह भी ठरविण्यात आले कि गेवराई नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए एक सक्षम ओबीसी उम्मीदवार को उतारा जाएगा और उसे विजयी बनाने के लिए पूरा ओबीसी समाज तन-

मन-धन से जुट जाएगा। बैठक में बलभीम बारगजे, परमेश्वर वाघमोडे, वंचित बहुजन आघाडी के पप्पू गायकवाड, भोले, राजेंद्र हराळे, रामेश्वर घुगे, अमोल आघाव, संभाजी देवकते, अब्दुल काज़ी, सय्यद आमेर, वर्धमान माने, पिंटू गर्जे, फौजी कडापे, पोतदार, बरकसे, राम रोकाडे, काळे, तेरे, सलमान सहित गेवराई शहर के ओबीसी समाज के अनेक कार्यकर्ता और समाजबंधु बड़ी संख्या में उपस्थित थे। गेवराई के प्रस्थापित राजनेताओं में मची हलचल! गेवराई नगराध्यक्ष पद के लिए ओबीसी उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारने और ओबीसी का वोट सिर्फ ओबीसी उम्मीदवारों को देने के इस महत्वपूर्ण निर्णय के बाद, स्थानीय स्वराज्य संस्था चुनाव में इसका असर पड़ने की आशंका से गेवराई शहर और तालुका के प्रस्थापित राजनेताओं में खलबली मच गई है और उनका सियासी संतुलन हिल गया है।

वोट चोरी के खिलाफ मुंबई यूथ कांग्रेस की मेट्रो और लोकल ट्रेनों में जन जागरूकता अभियान



मुंबई: संवाददाता
देश में चुनावों को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराना चुनाव आयोग की मूल जिम्मेदारी है, लेकिन लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण स्तंभ पर शक-सुबह के बादल गहराते जा रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने खुलासा किया है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग की मदद से वोट चोरी कर रही है। इसी पृष्ठभूमि में मुंबई यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष ज़ीनत

शबरीन की अगुवाई में यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों ने मुंबई मेट्रो और लोकल ट्रेनों में सूचनात्मक पैंफलेट बांटकर जनता में वोट चोरी के खिलाफ जन जागरूकता पैदा की। यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष ज़ीनत शबरीन और उनकी टीम ने घाटकोपर से साकी नाका और अंधेरी से गोरेगांव तक मेट्रो और लोकल में यात्रा करते हुए यात्रियों से सीधा संवाद किया और उन्हें चुनावी प्रक्रिया में कथित

धांधली तथा बीजेपी और चुनाव आयोग की भूमिका से अवगत कराया। सूचनात्मक पैंफलेट बांटते हुए जनता को वोट चोरी के विभिन्न तरीकों और उसके लोकतांत्रिक परिणामों के बारे में बताया गया, साथ ही देश के लोकतंत्र की रक्षा के लिए नागरिकों से इस अभियान में पूर्ण भागीदारी की अपील की गई। ज़ीनत शबरीन ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल

गांधी लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग की भ्रष्टाचारों को ठोस सबूतों के साथ बेनकाब किया है और उन तत्वों की पोल खोली है जो लोकतांत्रिक ढांचे का गला घोटने पर तुले हुए हैं। राहुल गांधी की इस लड़ाई में यूथ कांग्रेस पूर्ण शक्ति से उनके साथ खड़ी है और वोट चोरी के खिलाफ जन जागरूकता को अपना कर्तव्य समझती है।

उर्दू दैनिक तामीर के २५ वे साल में क़दम रखने पर एक और पेशकश

नगर परिषद चुनाव को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस कार्यालय में उम्मीदवारों की मुलाखतें, १०० से अधिक इच्छुकों ने जताई दायेदारी



बीड, ९ नवंबर: बीड शहर स्थित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में रविवार (९ नवंबर) को नगर परिषद चुनाव की पृष्ठभूमि पर नगरसेवक और नगराध्यक्ष पद के लिए २०० से अधिक इच्छुक उम्मीदवारों की मुलाखतें ली गईं। सुबह १० बजे शुरू हुई यह प्रक्रिया देर रात तक जारी रही। पार्टी को मिला यह उत्साही प्रतिसाद आगामी चुनाव में पार्टी की मजबूत स्थिति को दर्शाता है।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार स्वयं बीड जिले के पालकमंत्री होने के कारण उनका विशेष ध्यान स्थानीय स्वराज्य

संस्थाओं के चुनावों पर केंद्रित है। नगर परिषद चुनाव को देखते हुए प्रदेशाध्यक्ष सांसद सुनील तटकरे ने इच्छुक उम्मीदवारों की मुलाखतें लेकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे।

इसके अनुसार, पार्टी की मुलाखत समिति में जिलाध्यक्ष एड. राजेश्वर चव्हाण, पूर्व विधायक संजय दौंड, बीड विधानसभा अध्यक्ष डॉ. योगेश क्षीरसागर, राज्य प्रवक्ता भागवत तावरे, युवक जिलाध्यक्ष बळीराम गवते, शहराध्यक्ष अमर नाईकवाडे, अशोक हिंगे और फारुक पटेल शामिल थे। इस समिति के समक्ष देर रात तक नगरसेवक पद के लिए डेढ़ सौ से अधिक और

नगराध्यक्ष पद के लिए १६ इच्छुक उम्मीदवारों ने साक्षात्कार दिए। इस अवसर पर महिला आघाडी जिलाध्यक्ष एड. प्रज्ञा खोसरे, तालुकाध्यक्ष एड. राजेंद्र राऊत, कार्यालय चिटणीस महादेव धांडे सहित पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

नगराध्यक्ष पद के लिए १६ उम्मीदवारों ने दी मुलाखतें

नगराध्यक्ष का पद अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित है। इस पद के लिए ३५ इच्छुक उम्मीदवारों ने आवेदन खरीदे थे, जिनमें से १६ उम्मीदवारों ने साक्षात्कार दिए। इनमें प्रणिती राजेंद्र पवार,

सारिका विकास जोगदंड, पूजा भीमराव वाघचौरी, मीना भिमराव वाघचौरी, पूजा गणेश वाघमारे, क्रांती बाबुराव वडमारे, वंदना शरद साळवे, मीना अशोक वाघमारे, क्रांती प्रेम चांदणे, सविता मनोज मस्के, संगीता सुरेश वाघमारे, लता अविनाश शिरसट, छाया अशोक वीर, सुनिता उत्तम पवार, सुप्रिया माणिक वाघमारे और राधा चंद्रकांत थोरात शामिल हैं।

पार्टी कार्यालय परिसर में उमड़ी भारी भीड़ मित्रनगर चौक स्थित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के बाहर इच्छुक उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। देर रात तक साक्षात्कार की

प्रक्रिया जारी रही। प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद जिलाध्यक्ष एड. राजेश्वर चव्हाण पार्टी नेतृत्व को रिपोर्ट सौंपने वाले थे।

माहौल बदलने वाला है! मुस्लिम उम्मीदवारों की जबरदस्त तैयारी

बीड शहर में लगभग ४० प्रतिशत यानी करीब ६५ हजार मुस्लिम मतदाता हैं। अब तक इन मतदाताओं को स्वाभाविक रूप से वोट बैंक माना जाता था; लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। अजितदादा पवार की भूमिका और विकास के मुद्दे को देखते हुए मुस्लिम समाज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा, ऐसा कई मुस्लिम प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया है।

हाजरा बेगम ताहिर अली हाशमी को दिल्ली में नेशनल टीचर्स अवॉर्ड से सम्मानित किया गया



लातूर (रिपोर्ट: मोहम्मद मुस्लिम कबीर):

दिल्ली स्थित कौमी उर्दू कर्मचारी शिक्षक संघ की ओर से लातूर के नरगिस उर्दू स्कूल की सक्रिय शिक्षिका हाशमी हाजरा बेगम ताहिर अली को राष्ट्रीय स्तर का आदर्श शिक्षिका पुरस्कार प्रदान किया गया।

दिल्ली के गालिब अकादमी

में आयोजित एक भव्य समारोह में हाजरा बेगम ताहिर अली को मुख्य अतिथियों के हाथों सपासनामा (प्रशस्ति पत्र), पदक, शाल, और विशेष शिरोवस्त्र (शम्मा) पहनाकर सम्मानित किया गया।

हाजरा बाजी पूर्व प्रधानाध्यापक सैयद सलीमुद्दीन सर की पत्नी हैं। उर्दू भाषा के

प्रसार, विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण, तथा दीर्घकालीन शैक्षणिक सेवाओं के सम्मान में उन्हें इस पुरस्कार के लिए चुना गया।

उर्दू कर्मचारी शिक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वासीम अली गुजर, महाराष्ट्र राज्य के नाज़िम आबिद खान सर, और लातूर जिला अध्यक्ष मुहम्मद सलीम आलंद सर ने हाजरा बेगम ताहिर अली हाशमी के नाम की घोषणा की थी।

इस सम्मान के मिलने पर लातूर के शैक्षणिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों के लोगों सहित रिश्तेदारों ने हाजरा बेगम ताहिर अली हाशमी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ दी हैं।

ठाकरे के 'मातोश्री' पर ड्रोन की घेराबंदी!

जमीर काजी

मुंबई: स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनावों के कारण राज्य का माहौल गरमाया हुआ है, उसी बीच रविवार को इसे एक और नया मोड़ मिल गया। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बांद्रा स्थित 'मातोश्री' निवास पर अचानक एक ड्रोन द्वारा घेराबंदी किए जाने का नजारा देखकर हड़कंप मच गया। इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसके बाद ठाकरे परिवार की सुरक्षा पर सवाल उठते हुए उनके गुट और मनसे के नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया जताई। वहीं, एमएमआरडीए ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि पॉड टैक्सी सेवा के लिए पुलिस की अनुमति से सर्वे किया जा रहा था।

मातोश्री पर हमेशा उच्च स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था तैनात रहती है। उद्धव को न+ श्रेणी, आदित्य को न श्रेणी और रश्मी ठाकरे को ध श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। ऐसे में मातोश्री के आसपास ड्रोन के घूमने से हड़कंप मच गया। संभावित घुसपैठ को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की जा रही है। इस सिलसिले में ठाकरे गुट के विधायक अनिल परब ने कई गंभीर सवाल उठाए हैं। 'एक्स' पर एक पोस्ट में अनिल परब ने कहा, पुलिस को इस मामले की जांच करनी चाहिए। ड्रोन ऑपरेटर की पहचान और वीडियो के पीछे का उद्देश्य पता लगाया जाए। इसके पीछे कोई आतंकवादी पृष्ठभूमि तो नहीं? उन्होंने सवाल उठाया। यह ड्रोन किसका था और किस उद्देश्य से? ड्रोन से शूटिंग क्यों की गई? इसके पीछे कोई आतंकवादी पृष्ठभूमि तो नहीं? 'मातोश्री' जैसे न+ सुरक्षा वाले संवेदनशील क्षेत्र में बिना सूचना के ड्रोन से शूटिंग करना अत्यंत गंभीर मामला है, परब ने आरोप लगाया।

९ नवंबर को डॉ. इक़बाल उर्दू प्राइमरी स्कूल में विश्व उर्दू दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया



९ नवंबर को डॉ. अल्लामा इक़बाल की जयंती और विश्व उर्दू दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी अवसर पर डॉ. इक़बाल उर्दू प्राइमरी स्कूल में यह दिवस बड़े जोश और उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय की शिक्षिकाएँ चिरंती उम्मत-उस-समिना, पठान नसरीन, आयशा सिद्दीकी, और हाशमी शाइस्ता ने किया। इस अवसर पर सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और उर्दू भाषा की महत्ता, पवित्रता और मधुरता को अपने-अपने अंदाज़ में प्रस्तुत किया। विद्यार्थियों ने उर्दू में अपने काव्य और विचार प्रस्तुत कर भाषा के

प्रति प्रेम और जिम्मेदारी का भाव व्यक्त किया।

विद्यालय के प्रधानाध्यापक फ़हद सिद्दीकी सर ने भविष्य में भी उर्दू भाषा के संरक्षण और प्रसार के लिए इसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने और निरंतर प्रयास जारी रखने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।

अंत में, संस्था के सचिव जनाब चिरंती अब्दुससमद साहब ने विद्यार्थियों और शिक्षकों की मेहनत, लगन और उर्दू के प्रति समर्पण की सराहना करते हुए उन्हें हार्दिक बधाई दी।

बीड शहर कांग्रेस का मिशन ५२

बीड संवाददाता पार्टी के नेतृत्व में आज बीड शहर कांग्रेस कार्यालय में नगर परिषद २०२५ के चुनाव को लेकर बैठक आयोजित की गई। इस दौरान यह घोषणा की गई कि बीड शहर कांग्रेस पार्टी आगामी नगर परिषद चुनाव में ५२ सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी - यानी मिशन ५२।

कांग्रेस पार्टी के इच्छुक उम्मीदवारों की मुलाखत बीड जिले की माननीय सांसद रजनीताई पाटील और बीड जिला कांग्रेस अध्यक्ष राहुल भैया सोनवणे के निर्देशानुसार ली गई। इस प्रक्रिया में बीड नगरपालिका निरीक्षक अन्वर बापू



देशमुख, गणेश राऊत, शहर कांग्रेस अध्यक्ष परवेज कुरेशी, कांग्रेस नेता गणेश जवकर, डॉ. अमरेंद्र विद्यागर (भीमशक्ती जिला अध्यक्ष), तथा बीड शहर के प्रमुख पदाधिकारी

और कार्यकर्ता उपस्थित थे।

बीड शहर के २६ प्रभागों के प्रत्येक वार्ड से कांग्रेस टिकट के इच्छुक उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया गया। एक वार्ड के लिए दो

से चार उम्मीदवारों की मुलाखत हुई और इस प्रक्रिया में कार्यकर्ताओं का उत्साही प्रतिसाद देखने को मिला।

मुलाखत के दौरान प्रत्येक उम्मीदवार ने अपने विचार रखे। सभी की एकसमान भावना थी कि इस बार बीड शहर में १००% परिवर्तन होना निश्चित है।

उम्मीदवारों का कहना था कि आज समाज में जातिवादी राजनीति को रोकने और सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाला एकमात्र दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही है। समाज के वंचित वर्गों को अब यह स्पष्ट रूप से समझ में आ गया है।

बीड में शिवसेना उम्मीदवार चयन के लिए १० नवंबर को इंटरव्यू! सभी इच्छुक उम्मीदवार अपने कार्य रिपोर्ट सहित उपस्थित रहें-अनिलदादा जगताप

बीड (प्रतिनिधि): आगामी नगरपालिका चुनाव २०२५ की पृष्ठभूमि में शिवसेना की ओर से उम्मीदवार चयन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी अंतर्गत पार्टी द्वारा उम्मीदवारों के लिए आवेदन करने वाले इच्छुक उम्मीदवारों के इंटरव्यू सोमवार, १० नवंबर २०२५ को लिए जाएंगे।

इन इंटरव्यू का आयोजन लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे पुतले के समीप स्थित शिवसेना मध्यवर्ती कार्यालय, बीड में किया गया है। सभी इच्छुक उम्मीदवारों से अपील की गई है कि वे अपने कार्य अहवाल (परफॉर्मंस रिपोर्ट) सहित

सुबह ११:०० बजे से दोपहर ३:०० बजे के बीच इंटरव्यू के लिए उपस्थित रहें, ऐसा आवाहन शिवसेना जिल्हाप्रमुख अनिलदादा जगताप ने किया है।

इंटरव्यू के दौरान बीड शहर के शिवसेना के मुख्य पदाधिकारी और निरीक्षक उपस्थित रहेंगे। प्रत्येक प्रभाग (वार्ड) से अध्ययनशील, नेतृत्वक्षम, लोकाभिमुख और विकासभिमुख

चेहरा आगे लाने पर जोर दिया जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शक और अनुशासित ढंग से संपन्न होगी, ऐसा स्पष्टीकरण अनिलदादा जगताप ने दिया। उन्होंने कहा कि

नगरपालिका चुनाव के केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि यह शहर के भविष्य को आकार देने वाली प्रक्रिया है। पानी आपूर्ति, स्वच्छता, सड़कें, यातायात, बाजार व्यवस्था और नागरिक कल्याण जैसी जीवनावश्यक जबाबदारियाँ नगरपालिका प्रणाली पर निर्भर होती हैं। इसलिए सक्षम और विकासमुखी नेतृत्व का चयन अत्यंत आवश्यक है, ऐसा मत जिल्हाप्रमुख अनिलदादा जगताप ने व्यक्त किया।

अंत में, उन्होंने सभी इच्छुक उम्मीदवारों से अपील की कि वे समय पर उपस्थित रहकर शिवसेना की उम्मीदवार चयन प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता करें।

अहमदाबाद में ९३ म्यूनिसिपल स्कूल बंद: गुजरात कैसे पढ़ेगा? यह गुजरात मॉडल है जहां गरीब बच्चों के स्कूल बंद हो रहे हैं

हबीब शेख

अहमदाबाद: एक ओर राज्य सरकार स्कूली शिक्षा को और अधिक प्रभावी बनाने की बात करती है, तो दूसरी ओर अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधीन स्कूलों को बंद किया जा रहा है। कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि गरीब परिवारों के अधिकांश बच्चे इन्हीं स्कूलों में पढ़ते हैं, जो अब शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार, अहमदाबाद के विभिन्न क्षेत्रों में ९३ म्यूनिसिपल स्कूलों की इमारतें वर्षों से बंद पड़ी हैं। इन इमारतों में आंगनवाड़ी चलाने का फैसला किया गया है। शहर में लगभग २१०० आंगनवाड़ियां चलाई जाती हैं। इनमें से ७०० आंगनवाड़ियां म्यूनिसिपल स्कूल बोर्ड के अधीन स्कूलों में हैं। स्कूल बोर्ड की संपत्ति में ५४ इमारतें और स्कूल बोर्ड की संपत्ति में किराए की

इमारतों में चलाई जाने वाली ३९ इमारतें पिछले कुछ वर्षों से बंद पड़ी हैं। खाड़िया के अलावा, स्टैंडिंग कमेटी ने जमालपुर, बहमपुरा, एलिस ब्रिज और सरदार नगर वॉर्डों में ये इमारतें आंगनवाड़ियों को चलाने के लिए देने की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। स्कूल बोर्ड के प्रशासनिक अधिकारी लगधीर देसाई ने कहा कि स्कूलों को विलय किया जा रहा है क्योंकि कोट क्षेत्र में बच्चों की संख्या कम हो रही है।

अधिकांश स्कूल किराए की इमारतों में चलाए जा रहे हैं। बंद म्यूनिसिपल स्कूलों में आंगनवाड़ियों को चलाने के फैसले से कॉर्पोरेशन को सालाना १० करोड़ रुपये की बचत होगी। सरकारी स्रोतों ने बताया है कि बंद स्कूलों की कुछ इमारतों को मामूली मरम्मत के बाद दोबारा उपयोग किया जा सकता है। शहर की २१०० आंगनवाड़ियों



में से ७०० किराए की इमारतों में चल रही हैं, जिनके सालाना किराए पर १००० रुपये की बचत का दावा किया जाता है।

बंद म्यूनिसिपल स्कूल की इमारत किस क्षेत्र में है? शहर के सरदार नगर, असारवा, कबीर



नगर, सागेपुर के साथ-साथ कलपुर, दरियापुर और जमालपुर क्षेत्रों में म्यूनिसिपल स्कूल की कुछ इमारतें वर्षों से बंद हैं। शाहपुर, सरसपुर, गोमतीपुर, बापू नगर, खोखरा, घोड़ा सर, बहमपुर, रायखेड़ और मेधानी नगर क्षेत्रों में एक-एक स्कूल

खस्ताहाल होने के कारण बंद है।

जिन स्कूलों को बंद किया गया था, उनमें से कुछ खाड़िया में लखा पटेल के तालाब में हैं। वर्तमान में बंद म्यूनिसिपल स्कूलों की इमारतों में आंगनवाड़ियों को चलाने के फैसले से कॉर्पोरेशन को १.५-२ करोड़ रुपये की बचत होगी, जो इसे हर महीने किराए के रूप में देना पड़ता है।

अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के एक अधिकारी ने कहा कि यद्यपि गरीब परिवारों के बच्चों को सरकारी शैक्षणिक सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है, लेकिन ये ९१ स्कूलों की इमारतें सरकारी हैं। ये संपत्तियां लंबे समय से बंद होने के कारण खस्ताहाल हो गई हैं, जिसके कारण सरकार की करोड़ों रुपये की निवेश बर्बाद हो रही है। हकीकत यह है कि स्कूल बोर्ड के नए स्कूल शुरू करने के दावों के बावजूद इतनी

बड़ी संख्या में स्कूल बंद हैं। हालांकि, विपक्ष नेता शहजाद खान ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह स्कूल बोर्ड प्रशासन की नाकामी को दर्शाता है। शिक्षा में संचानात्मक सुधारों के बजाय काम कर रहे स्कूलों को भी बंद करने की ओर धकेला जा रहा है। ऊपर उल्लिखित जानकारी इसे साबित करती है। वर्तमान में बंद स्कूलों के कमरों को अन्य गतिविधियों के लिए क्यों उपयोग किया जा रहा है? यह जांच का विषय है। कांग्रेस ने बोर्ड से मांग की है कि ९१ बंद स्कूलों को अगले ९० दिनों में पूरी तरह सक्रिय बनाने के लिए एक निश्चित एक्शन प्लान की घोषणा की जाए। बंद स्कूलों की इमारतों की युद्ध स्तर पर मरम्मत की जाए और छात्रों के बैठने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं, वॉशरूम, पीने के पानी की सुविधाएं तुरंत की जाएं।